प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2018**

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 75वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.09.2013 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये मल्टीसैक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद बलरामपुर** के विकास खण्ड-गैसड़ी, गैदास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिए केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(19)/2012-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-48/52-1-2014-01(130)/13, दिनांक 25 फरवरी, 2014 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त योजनाओं के निर्माण के लिए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/42/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 02.01.2018 द्वारा उक्त योजनाओं हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 337.27 लाख में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 252.97 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 126.47 लाख (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख सैतालिस हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 42.165 लाख (रूपये बयालिस लाख सोलह हजार पांच सौ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 168.635 लाख (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(के0-75/रा0-25)												(रू0 लाख में)
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	भारत सरकार द्वारा प्रायोजना की स्वीकृत लागत	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **द्वितीय** किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
										केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**बलराम पुर**	**विकास खण्ड-गैसड़ी** के जनकपुर में पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण	01	98.94	74.21	24.73	98.94	132.00	49.47	37.10	12.37	49.47
2	,,	**विकास खण्ड-गैसड़ी** के डीहरूप सिंह में रा0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	01	40.45	30.34	10.11	40.45	59.94	20.225	15.17	5.055	20.225
3	,,	**विकास खण्ड-गैदास बुजुर्ग** के परसौना में पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण	01	98.94	74.21	24.73	98.94	132.00	49.47	37.10	12.37	49.47
4	,,	**विकास खण्ड-रेहरा बाजार** के ओवरीडीह में पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण	01	98.94	74.21	24.73	98.94	132.00	49.47	37.10	12.37	49.47
		योग	**04**		**252.97**	**84.30**	**337.27**	**455.94**	**168.635**	**126.47**	**42.165**	**168.635**

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(18) में वित्त (आय-व्ययक)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 द्वारा संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की गयी है :-

"केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति, योजना में केन्द्रांश की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी।"

परन्तु यदि प्रशासकीय विभाग केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं, तो प्राप्त केन्दांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर -138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि 09 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत पी0एच0सी0/रा0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय की डिजाइन वही होगी, जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है।

7- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुदान ग्राही द्वारा एक पृथक लेखा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

14- कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय।

http://sirasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

15- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

17- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण(के0 60-रा0 40-के0+रा0)**-24--वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं संशोधित आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दि0 24.04.2018 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-164/दस-2018, दिनांक 28.06.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या-763(1)/बावन-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (परीक्षा विभाग), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

6- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थलों की सूची सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से प्राप्त कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले प्रश्नगत पी0एच0सी0 के चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण की सूची कार्यदायी संस्था एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-4

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in